



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 331]
No. 331]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 1989/आषाढ़ 5, 1911
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 1989/ASADHA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिलेखना

नई दिल्ली, 26 जून, 1989

बीमा

भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कुछ

निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989

सा.का.नि. 643 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों के कारबार निर्वहन से संबंधित सेवा के कुछ निबंधनों और शर्तों का विनियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कुछ निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 है।

(2) इन नियमों में जो अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय वे 1 अप्रैल, 1988 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अभिप्रेत है,

(ख) “तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक” से नियम 7 के उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (1) में उपर्युक्त रीति में संगणित अवधेयता के प्रयोजन के लिए किसी विकास अधिकारी को लागू होने वाला वार्षिक पारिश्रमिक अभिप्रेत है,

(ग) “वार्षिक पारिश्रमिक” से अभिप्रेत है : मूल वेतन, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, महंगाई भत्ते, तथा अन्य सभी भत्ते और

साम-निरपेक्ष भागीदारी या अनुग्रह बोनम जो मूल्य निर्धारण वर्ष में विकास अधिकारी को देय या मिला है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यय भी है जो उस वर्ष के दौरान याता, आवासीय, टेलीफोन, बीमा प्रीमियम तथा मोटर वाहन के संबंध में उसे निगम द्वारा देय है या जिसकी जाबत निगम ने उसकी प्रतिपूर्ति की है जो निगम ने उपगत किया है, किन्तु इसके अन्तर्गत नियम 17 के अनुसार उसे संबल प्रेरणा बोनस या प्रतिरिक्त परिवहण सवारी भत्ता नहीं है,

(घ) "मूल्य निर्धारण तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:—

(1) 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् नियुक्त किसी विकास अधिकारी के संबंध में,—

(अ) अपनी सेवा काल के प्रथम वर्ष में, उस मास का प्रथम दिन, जो उस मास के बाद आता है, जिसमें वह अपनी नियुक्ति की तारीख से बारह मास की सेवा पूरी करता है; और

(आ) अपने सेवाकाल के प्रत्येक पश्चात्तवर्ती वर्ष में, पिछली मूल्य निर्धारण तारीख से बारह मास का सेवाकाल पूरा होने के बाद ठीक अगले मास का प्रथम दिन।

(2) 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व नियुक्त किसी विकास अधिकारी के संबंध में,—

(अ) 1 अप्रैल, 1988 से अपने सेवा काल के प्रथम वर्ष में,

(1) 1 अप्रैल, 1988, यदि वह 31 मार्च, 1988 को बारह मास की सेवा पूरी करता है, या

(2) उस मास का प्रथम दिन, जो उस मास के बाद आता है जिसमें वह उस तारीख से बारह मास की सेवा पूरी करता है जिसकी उसकी अंतिम वार्षिक वेतनवृद्धि भारतीय जीवन बीमा नियम (कर्मचारीवृत्त) नियम, 1960 के नियम 56 के उपनियम (2) के अनुसार प्रोद्भूत हुई थी (चाहे निर्माजित की गई हो या नहीं) यदि उसने 1 मार्च, 1988 को बारह मास या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली थी; और

(आ) अपने सेवाकाल के प्रत्येक पश्चात्तवर्ती वर्ष में, पिछली मूल्य निर्धारण तारीख से बारह मास का सेवाकाल पूरा होने के बाद ठीक अगले मास का प्रथम दिन;

(इ) "मूल्य निर्धारण वर्ष" से अभिप्रेत है, दो लगा-तार मूल्य निर्धारण तारीखों के बीच की अवधि और उपखण्ड (1) की मध (अ) के अनुसार अभिनिश्चित मूल्य निर्धारण तारीख से पहले पढ़ने वाली बारह मास की अवधि, और खण्ड (घ) के उप खण्ड (2) की मध (अ) के अनुसार अभिनिश्चित मूल्य निर्धारण तारीख से पहले पढ़ने वाली सेवा की बारह मास की प्रत्येक अवधि भी मूल्य निर्धारण वर्ष होगी;

(ज) "लागत अनुपात" से विकास अधिकारी के संबंध में वह अनुपात अभिप्रेत है जो किसी वर्ष में उसके वार्षिक पारिश्रमिक या उसके तत्पर्य वार्षिक पारिश्रमिक, यदि लागू होता हो, का उस वर्ष के आदेय प्रीमियम से है और ऐसे आदेय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है;

(झ) "वेतन-ह्रास" से एक या अधिक अवसरों पर वेतनमान में एक या अधिक प्रक्रमों द्वारा मूल वेतन में कमी करना अभिप्रेत है;

(ज) "विकास अधिकारी" से विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त वर्ग 2 का निगम का कोई पूर्ण-कालिक वेतन भोगी कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो 1 सितम्बर, 1956 को निगम का कर्मचारी बना था और विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है;

(झ) "अवप्रेरणा" से सवारी भत्ता में कमी करना या अवप्रेरणा-सारणी में यथा उपबंधित वेतन-वृद्धि का न दिया जाना या वेतन ह्रास अभिप्रेत है,

(ञ) "आदेय प्रीमियम" से अभिप्रेत है, विकास अधिकारी संगठन के अधिकारियों द्वारा प्राप्त कारबार के संबंध में निगम द्वारा प्राप्त प्रथम वर्ष के प्रीमियम का वह अनुपात जो समय-समय पर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय और सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष में समायोजित किया जाए।

(ट) नीचे दो गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट व्यापार क्षेत्र में कार्यरत विकास अधिकारी के संबंध में मूल्य निर्धारण वर्ष के बारे में "व्यय सीमा" से (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यय सीमा-सारणी कहा गया है) अभिप्रेत है, उस तालिका के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट उस वर्ष के आदेय प्रीमियम का प्रतिशत:

व्यय-सीमा सारणी

यदि विकास अधिकारी व्यापार क्षेत्र में कार्यरत है	आदेय प्रीमियम का प्रतिशत
(1)	(2)
क	22 प्रतिशत
ख	23 प्रतिशत
ग	24 प्रतिशत
घ	25 प्रतिशत
ङ.	26 प्रतिशत

(टिप्पणी:—किसी भी मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी की व्यय-सीमा उस वर्ष के आदेय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। यदि किसी विकास अधिकारी का उस वर्ष का वार्षिक पारिश्रमिक व्यय-सीमा से अधिक है तो यह कहा जाता है कि उसने व्यय-सीमा पार कर ली है; ऐसे अधिक्य या उस अनुपात को, जो उसके वार्षिक पारिश्रमिक का उस वर्ष के आदेय प्रीमियम से है, ऐसे आदेय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है।

(ठ) विकास अधिकारी के सवर्ध में "व्यापार क्षेत्र" से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जिसमें वह विकास अधिकारी को रूप में काम करने के लिए तैनात है और ऐसा विकास अधिकारी व्यापार क्षेत्र में कार्यरत तब कहा जाता है जब वह,—

(क) किसी नगर, शहरी सीमा या कस्बे में काम कर रहा है, जिसकी अभिनिश्चित जनसंख्या 10 लाख से अधिक है;

- (ख) किसी नगर, शहरी सीमा या कस्बे में काम कर रहा है, जिसकी अभिनिश्चित जनसंख्या 4 लाख या उससे अधिक, किन्तु 10 लाख से अधिक नहीं है,
- (ग) किसी नगर, शहरी सीमा या कस्बे में काम कर रहा है। (जो ग्रामीण क्षेत्र या प्रतिग्रामीण क्षेत्र नहीं है) जिसकी अभिनिश्चित जनसंख्या 4 लाख से कम है ;
- (घ) किसी ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है, और
- (ङ) यदि वह स्पष्टीकरण (4) में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिग्रामीण क्षेत्र या किसी पहाड़ी क्षेत्र में कार्य कर रहा है या किसी ऐसे अन्य पहाड़ी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे केन्द्रीय सरकार, निगम के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण :—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,—

- (1) "अभिनिश्चित जनसंख्या" से भारत सरकार की सबसे अंतिम जनगणना रिपोर्ट के आधार पर अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है,
- (2) विकास अधिकारी तब "ग्रामीण क्षेत्र" में कार्यरत कहा जाता है जब उसका मुख्यालय किसी ऐसे स्थान पर है, जिसकी अभिनिश्चित जनसंख्या 30,000 या उससे कम और उसके व्यापार क्षेत्र की अभिनिश्चित जनसंख्या 1,00,000 से अधिक नहीं है,
- (3) विकास अधिकारी तब "प्रतिग्रामीण क्षेत्र" में कार्यरत कहा जाता है जब उसका मुख्यालय किसी ऐसे स्थान पर है, जिसकी अभिनिश्चित जनसंख्या 10,000 या उससे कम और उसके व्यापार क्षेत्र की अभिनिश्चित जनसंख्या 60,000 से अधिक नहीं है ;
- (4) विकास अधिकारी "पहाड़ी क्षेत्र" में कार्यरत तब कहा जाता है जब उसका मुख्यालय भूतत् समुद्री स्तर से ऊपर 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊँचाई पर है, जिसकी अभिनिश्चित जनसंख्या 20,000 या उससे कम है और उसके व्यापार क्षेत्र की अभिनिश्चित जनसंख्या 75,000 से अधिक नहीं है।

(ड) "पूर्वगामी वर्ष" या "सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष" से, सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है,

(ड) "विहित व्यय-सीमा" या "विहित लागत अनुपात" से नियम 4 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के परन्तुक के अनुसार अभिनिश्चित बढ़ाई गई व्यय-सीमा अभिप्रेत है जहाँ ऐसी व्यय-सीमा विकास अधिकारी पर लागू होती है, या जहाँ वह उस पर लागू नहीं होती है वहाँ पद से वह व्यय-सीमा अभिप्रेत होगी जो उसको लागू होती है।

- (ण) "सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख" से वह मूल्य निर्धारण तारीख अभिप्रेत है, जो उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी के कार्यपालन का, इन नियमों के अधीन किसी भी प्रयोग के लिए, मूल्यांकन किया जाता है या कर्मचारिवृन्द नियमों के अधीन इस पर किया गया था,
- (त) "सेवा" से वह अवधि अभिप्रेत है जो विकास अधिकारी के रूप में कर्तव्य पूरा करते हुए तथा कर्मचारिवृन्द नियमों के नियम 69(4) के अधीन भत्ता की गई असाधारण छुट्टियों सहित, अन्य छुट्टियों पर बिताई गई है,
- (द) "उत्तरवर्ती वर्ष" से सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है,
- (ध) "अवप्रेरण सारणी" से नियम 7 के उपनियम (1) के नीचे दी गई सारणी अभिप्रेत है,
- (न) "बढ़ाई गई व्यय सीमा सारणी" से नियम 4 के उपनियम (2) के नीचे दी गई सारणी अभिप्रेत है,
- (प) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और जो कर्मचारिवृन्द नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके कर्मचारिवृन्द नियमों में हैं।

पदावधि

इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विकास अधिकारी, उसी अवधि तक और उसी रीति में पद धारण करेगा जिसमें कि निगम के अन्य कर्मचारी धारण करते हैं।—

परन्तु वह स्वयं का लागू व्यय सीमा का अनुपालन करेगा

परन्तु यह और कि किसी पुष्प विकास अधिकारी की सेवाएं ऐसे भ्रष्ट कारबार उत्पादन के आधार पर जिससे उसको लागू व्यय सीमा से अधिक लागत अनुपात हुआ है, समाप्त नहीं की जाएगी जब तक कि नियम 7 में यथा उपबन्धित व्यय सीमा का अनुपालन करने का उसे अवसर प्रदान न किया गया हो।

4 विकास अधिकारियों को लागू व्यय सीमा

(1) किसी विकास अधिकारी को लागू व्यय सीमा वह होगी जो व्यय सीमा की सारणी में विनिर्दिष्ट है।

परन्तु जहाँ किसी विकास अधिकारी ने सुसंगत मूल्य निर्धारण 1987 के प्रारम्भ के समय विकास अधिकारी के रूप में दस वर्ष से अधिक की सेवा की है, वहाँ सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए उसको लागू व्यय सीमा एक प्रतिशत तक बढ़ाई गई उसके व्यापार क्षेत्र को लागू व्यय सीमा होगी यदि सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ के समय या उसके पूर्व, उसने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और यदि उसने 52 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो ऐसी व्यय सीमा में दो प्रतिशत तक और यदि उसने 54 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो 3 प्रतिशत तक 1 अक्टूबर, 1987 से वृद्धि की जाएगी।

(2) जहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरावलोकन) नियम, 1986 के नियम 10 में अन्तर्निष्ठ उपबन्धों के अनुसरण में किसी विकास अधिकारी को दिया गया साम्यापूर्ण अनुतोष उसके वार्षिक पारिश्रमिक का भाग है, वहाँ नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण वर्षों के लिए उसको लागू व्यय सीमा वह होगी जो सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रतिशत तक 1 अक्टूबर, 1987 से बढ़ाई गई है:

बढ़ाई गई व्यय सीमा की सारणी

निम्नलिखित धाराओं में बारह मासों के किसी प्रथम दिन को प्रतिगत प्रारंभ होने वाले मूल्य निर्धारण वर्ष

(1)	(2)
(क) अक्टूबर 1986—सितम्बर, 1987	2 प्रतिशत
(ख) अक्टूबर, 1987—सितम्बर, 1988	2 प्रतिशत
(ग) अक्टूबर, 1987—सितम्बर, 1989	1 प्रतिशत

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट बढ़ाई गई व्यय सीमा व्यापार श्रेणियों 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' की बाबत 1 अक्टूबर, 1987 को या उनके पश्चात् पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को देय मूल्य निर्धारणों को लागू होगी :

परन्तु 1 अक्टूबर, 1987 को या उनके पश्चात् कितु अप्रैल, 1988 के पूर्व पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीखों को देय मूल्य निर्धारणों की बाबत व्यय सीमा का अनुपालन करने का अवसर सुसंगत समय पर यथा प्रवृत्त कर्मचारीवृन्द नियमों की अनुसूची 3 में परा 5 के नीचे सारणी के अनुसार विनियमित होगा ।

(4) उपनियम (1) और उपनियम (2) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट बढ़ाई गई व्यय सीमा व्यापार श्रेणियों "क" की बाबत 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को देय मूल्य निर्धारणों को लागू होगी ।

(5) उपनियम (1) या उपनियम (2) के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी अवप्रेरणा सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता या नियम 7 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता में वृद्धि नहीं की जाएगी ।

5. वेतन वृद्धियाँ

(1) किसी विकास अधिकारी द्वारा वेतन वृद्धियाँ साधारणतया कर्मचारीवृन्द नियमों के नियम के अनुसार सामान्य क्रम में प्राप्त की जाएंगी जब तक कि वह अधिकतम ग्रेड में नहीं पहुँच गया हो या वेतन वृद्धि नियम 7 या नियम 10 के अनुसार अनुज्ञात नहीं की जा सकती हो या कर्मचारीवृन्द नियमों के नियम 39 के अधीन किसी अनुज्ञातनात्मक अध्युपाय के रूप में नहीं रोकी जा सकती हो ।

(2) जहाँ किसी वर्ष में किसी विकास अधिकारी को कोई वेतन वृद्धि अवप्रेरणा के रूप में नियम 7 के अनुसार नहीं दी जाती है, वहाँ ऐसी वेतन वृद्धि नियम में अस्तिविष्ट उपबंधों के अनुसार के विना किसी पश्चात्कर्ती वर्ष में उसे नहीं दी जाएगी ।

6. सबारी मत्ता :

हर एक विकास अधिकारी ऐसे सबारी मत्ता का हकदार होगा जो समय समय पर नियम द्वारा दिया जाए :

परन्तु किसी वर्ष में विकास अधिकारी को अनुमेय सबारी मत्ता नियम 7 के उपबंधों के अधीन होगा ।

7. व्यय सीमा के अनुपालन का अवसर

(1) जहाँ पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में किसी विकास अधिकारी का वार्षिक पारिश्रमिक व्यय सीमा से अधिक है वहाँ उसकी सेवाएं मात्र उस आधार पर समाप्त नहीं की जाएंगी यदि उसका मामला अवप्रेरणा सारणी में यथा उपबधित सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से नियम 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अवप्रेरणा बेकर निपटाया जा सकता है जिससे कि उसे व्यय सीमा के अनुपालन करने का अवसर प्रदान किया जा सके ।

परन्तु अवप्रेरणा सारणी के अनुसार अवप्रेरणा देने के प्रयोजन के लिए उसके कार्यपालन का तबसे वार्षिक पारिश्रमिक और उसको लागू विहित व्यय सीमा के प्रति निर्देश से मूल्य निर्धारण किया जाएगा ।

अवप्रेरणा—सारणी

क्रम सं.	जहाँ तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक विहित व्यय सीमा से अधिक है या लागत अनुपात विहित सीमा से अधिक है ।	अवप्रेरणा जहाँ सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक विहित व्यय सीमा से अधिक है या लागत अनुपात विहित सीमा से अधिक है ।	प्रथम अवसर पर	द्वितीय अवसर पर	तृतीय अवसर पर	चतुर्थ अवसर पर	पंचम अवसर पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	2 प्रतिशत से अधिक नहीं (परन्तु यह तब जबकि मूल निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक नहीं है)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	
	2 प्रतिशत से अधिक किन्तु 6 प्रतिशत से अधिक नहीं (परन्तु यह तब जबकि मूल निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक नहीं है)	स.भ. में 30 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 50 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	
	6 प्रतिशत से अधिक किन्तु 9 प्रतिशत से अधिक नहीं (परन्तु यह तब जबकि मूल निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक नहीं है)	स.भ. में 50 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई वेतन वृद्धि नहीं तथा एक वेतन ह्रास ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 प्रतिशत से अधिक (परन्तु यह तब जबकि मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक नहीं है)	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास
जहाँ मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक है किन्तु 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास
जहाँ मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है।	स.भ. में 60 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 70 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास	स.भ. में 80 प्रतिशत कटौती और कोई बेतन बूढ़ि नहीं तथा एक बेतन-ह्रास

टिप्पण : इस सारणी के प्रयोजनों के लिए —

- (क) "स.भ. में कटौती" से सवारी भत्ता में कमी करना अभिप्रेत है ;
 (ख) "कोई बेतन बूढ़ि नहीं" से बेतन बूढ़ि का न दिया जाना अभिप्रेत है ;
 (ग) "बेतन-ह्रास" से एक प्रथम तक मूल बेतन में कमी करना अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण : इस उपनिधम के प्रयोजनों के लिए,—

(i) (क) अवश्रेणा के अधिनियम के लिए मूल निर्धारण के प्रयोजनों के लिए तबसे बाह्यक परिश्रमिक प्रवृत्ति रूप में अभिनिश्चित किया जाएगा और मूल बेतन, विशेष बेतन, व्यक्तिगत बेतन, पृथक बेतन, महंगाई भत्ता और अन्य सभी भत्तों का 12 गुना समस्त, जाणूना जिसके अन्तर्गत सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख के पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के प्रथम दिन को किसी विकास अधिकारी को अनुसूच्य सवारी भत्ता और ल.भ. निरोध भागीदारी या अनुसूच्य भोतन जो मूल निर्धारण वर्ष के दौरान उसको देय है या मिला है और इसके अन्तर्गत ऐसे कुल व्यय भी है जो याता, आवासीय टेलीफोन और धीम, प्रीमियम तथा मोटर वानों पर करों के संबंध में उसे देय है या उसकी उसे प्रतिपूर्ति की गई है या वे उन पर उपगत हुए हैं :

परन्तु यदि उसके सवारी भत्ता में उसके द्वारा, कोई दान अर्जित करने या किसी निम्न प्रकार के दान को कृत करने के परिणामस्वरूप अथवा सवारी भत्ते के किसी पुनरीक्षण के कारण पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई बूढ़ि हुई है तो उस वर्ष के दौरान उसका संवत् बढ़ाया गया सवारी भत्ता उसका लागू तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक निकालने के लिए जोड़ा जाएगा।

(ख) पूर्वगामी रीति में तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक की संगणना की रीति अवश्रेणा के प्रयोजन के लिए, 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को देय सभी मूल निर्धारणों को शामिल करनी :

परन्तु सुसंगत मूल निर्धारण तारीखों को जो 1 अप्रैल, 1989 को या उसके पश्चात् पड़ सकती है, देय मूल निर्धारणों के लिए यदि उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित पूर्वगामी वर्ष जिसे इस उपखंड में इसके पश्चात् 'सुसंगत वर्ष' कहा गया है के लिए तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक सुसंगत वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए उसी रीति में संगणित तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक से 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो सुसंगत वर्ष के लिए तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक सुसंगत वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती ऐसे मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए उपखंड (क) के अनुसार संगणित तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक का 110 प्रतिशत समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि विकास अधिकारी सवारी भत्ते में उसके द्वारा कोई दान अर्जित करने या किसी निम्न प्रकार के दान को कृत करने के परिणामस्वरूप अथवा सवारी भत्ते के किसी पुनरीक्षण के कारण पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई बूढ़ि हुई है तो उस वर्ष के दौरान उसको संवत् बढ़ाया गया सवारी भत्ता उसको लागू तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक निकालने के लिए जोड़ा जाएगा।

(ग) उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) में किसी दान के होते हुए भी जहाँ किसी विकास अधिकारी ने विकास अधिकारी के रूप में 10 वर्ष से अधिक की सेवा की है और सुसंगत मूल निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ के समय 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वहाँ उसके कार्यपालन का उस मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए जिस के प्रारम्भ के समय उसने इस खंड में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं, अवश्रेणा के अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसको लागू वार्षिक पारिश्रमिक के प्रतिनिर्देश से प्रारम्भिक रूप से अभिनिश्चित रूप में मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसा वार्षिक पारिश्रमिक उसके मामले में तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक भी समझा जाएगा :

परन्तु ऐसे किसी विकास अधिकारी की बाबत जिसने 1 अप्रैल, 1988 से पूर्व किसी तारीख को या किसी मूल निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ के समय या उसके पूर्व पूर्ण सेवा और आयु के बारे में अपेक्षाओं की पूर्ति की है, तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले सुसंगत मूल निर्धारण वर्ष में प्रवृत्ति रूप से अभिनिश्चित उसकी लागू वार्षिक पारिश्रमिक इस रूप में माना जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि विकास अधिकारी सवारी भत्ते में उसके द्वारा कोई दान अर्जित करने या किसी निम्न प्रकार के दान को कृत करने के परिणामस्वरूप अथवा सवारी भत्ते के किसी पुनरीक्षण के कारण पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई बूढ़ि हुई है तो उसको संवत् बढ़ाया गया सवारी भत्ता ऐसे पश्चात् वर्षों में और उसके पश्चात् उसका तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक निकालने के लिए जोड़ा जाएगा।

(घ) पूर्वगामी उपखंडों में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी मूल्य निर्धारण वर्ष में किसी विकास अधिकारी का वार्षिक पारिश्रमिक पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट रीति में संगणित तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक से कम या

तो ऐसा वार्षिक पारिश्रमिक अवधेयता के अधिनियम के लिए मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उस मूल्य निर्धारण वर्ष में उसको लागू तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक संपत्ति जाएगा।

(इ) जहाँ विकास अधिकारी को सेवाओं के निबंधनों और शर्तों के साधारण पुनरीक्षण से संबंधित किन्हीं नियमों के अनुसरण में बेतनमान या भत्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है वहाँ पूर्वगामी उपबंधों के अधीन तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक की संगणना अधिनियम की धारा 48 के अधीन जारी किए गए ऐसे नियमों के उपबंधों के अधीन होगी।

(ख) इस खण्ड के आधार पर तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक की संगणना केवल अवधेयता के प्रयोजन के लिए होगी और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए वार्षिक पारिश्रमिक को हिसाब में लिया जाएगा।

(छ) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (i) के प्रयोजनों के लिए पारिश्रमिक का जिसके लिए कर्मचारी इन नियमों के अधीन सामान्य अनुक्रम में पात्र है, परिकल्पना या उसकी संगणना द्वारा पारिश्रमिक प्रथमिक रूप से अधि-निश्चित किया जाएगा और उसके लिए विशेष परिस्थितियों के अधीन, जैसे निवृत्ति, भ्रष्टाचार छुट्टी या प्रथम बेतन पर बीमारी छुट्टी या किसी अन्य कारणवश पारिश्रमिक की किसी कटौती, कमी या उसके किसी भाग को रोकने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) अवधेयता सारणी का लागू किया जाना नियम 9 में अस्तित्व में उपबंधों के अधीन होगा, परन्तु यह तब जबकि विकास अधिकारी की सेवाओं को इस नियम के उप नियम (2) या उप नियम (8) के अधीन समाप्त नहीं किया जा सकता।

(iii) अवधेयता सारणी के प्रयोजन के लिए, किसी विकास अधिकारी का तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक क्रमिक अवसर पर विहित व्यय सीमा से अधिक तब माना जाएगा जब ऐसा पारिश्रमिक दो लगातार मूल्य निर्धारण वर्षों में ऐसी व्यय सीमा से अधिक रहता है, भले ही व्यय सीमा से अधिक का प्रतिशत निम्न हो और किसी मूल्य निर्धारण वर्ष को भी जिसमें विकास अधिकारी व्यय सीमा पार करता है, भले ही वहाँ कोई अवधारणा न हो, यह अधिनिश्चित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा कि क्या क्रमिक अवसरों पर व्यय सीमा पार हुई है और क्रमिक अवसरों पर अवधेयता सुसंगत मूल निर्धारण तारीख के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में विहित व्यय सीमा के अधिकार के अनुरूप होगी।

(iv) अवधेयता सारणी को निरंतर लागू किया जाएगा, यदि विहित व्यय सीमा का अनुपालन करने के पश्चात् विकास अधिकारी किसी पश्चात्पूर्व तारीख को पुनः इसे पार कर जाता है।

(2) यदि उपनियम (1) में अस्तित्व में उपबंधों के लागू किए जाने के फलस्वरूप निकाला गया मूल बेतन विकास अधिकारी के बारे में लागू श्रेष्ठ के न्यूनतम से जो कम पड़ता है तो उसका मूल बेतन ऐसे न्यूनतम पर हो नियत कर दिया जाएगा :

परन्तु इस उपनियम के अधीन न्यूनतम पर मूल बेतन का नियत किया जाना विकास अधिकारी की सम्पूर्ण सेवा के दौरान एक से अधिक बार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और यदि किसी दूसरे अवसर पर इस प्रकार निकाला गया मूल बेतन ऐसे न्यूनतम से कम पड़ता है तो उसकी सेवाएं नियम 8 के अनुसार समाप्त की जा सकेंगी।

(3) (क) जहाँ किसी विकास अधिकारी के मूल बेतन में उप-नियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कमी की जाती है या यह नियत किया जाता है (जैसे इसमें इसके पश्चात् "पुनरीक्षित मूल बेतन" कहा गया है) वहाँ उसे केवल ऐसे भत्ते और अन्य फायदे अनुज्ञात होंगे जो उस मूल बेतन पर उसे अनुज्ञेय हैं;

(ख) जहाँ उसके सवारी भत्ते में कमी की गई है, वहाँ वह केवल ऐसे सवारी भत्ते का हकदार होगा जो पुनरीक्षित मूल बेतन के आधार पर इस प्रकार कम किया गया है।

परन्तु वार्षिक पारिश्रमिक का सठ्ठारतन तो वैयक्तिक कला देकर औषु न किसी अन्य प्रकार से दिया जाएगा और व्यय सीमा का तपश्चात् उसके द्वारा पालन करने के पारिणामस्वरूप पिछली अवधि के लिए बेतन का कोई बकाया या कोई भत्ता सम्भाव्य नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1), (2), (3) के उपबंधों की कार्यविधि करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और वह सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष की समाप्ति के पचा मोक्ष पश्चात् उक्त उपनियमों में विनिश्चित विषयों को अवधारित करेगा :

परन्तु सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी इस नियम के अधीन किसी विषय का विनिश्चय करने के पूर्व विकास अधिकारी को अवधारित करने का अवसर प्रदान करेगा,।

(5) जहाँ उपनियम (4) के परन्तु के अधीन अधिप्राप्त अवधार-वेदन से—

(क) आवेय प्रीमियम या अन्य आंकड़ों की संगणना में किन्हीं वास्तविक प्रशुद्धियों का पता चलता है, तो सक्षम प्राधिकारी पुनरीक्षित आंकड़ों के अनुसार अपने आवेय सीमा तक अपने विनिश्चय को पुनरीक्षा करेगा और अवधारित का निपटाने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा;

(ख) यदि व्यय सीमा में जोन को उचित ठहराने के लिए अवधारित से किसी ऐसे कारण का पता चलता है, जो विकास अधिकारी के नियंत्रण के पर था जैसे दुर्घटना या बीमारी, और यदि वह तर्क देता है उस आधार पर अवधेयता का अधिनियम प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए तो सक्षम प्राधिकारी उस अवधार-वेदन को विनिश्चय के लिए जोन प्रबंधक को भेजेगा।

(6) यदि जोन प्रबंधक का समाधान हो जाता है कि अवधारित में कोई गुणगुण है तो वह मामले को परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे।

(7) ऐसा विकास अधिकारी जिसका अवधारित जोन प्रबंधक द्वारा नापुर्ण कर दिया गया है, उस मामले की बाबत प्रत्यक्ष को एक आपन प्रस्तुत करेगा।

(8) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी पूर्ववर्ती वर्ष में (जैसे इस उपनियम में इसके पश्चात् "सुसंगत वर्ष" कहा गया है) किसी विकास अधिकारी का तदर्थ वार्षिक पारिश्रमिक उस वर्ष के आवेय प्रीमियम के 50 प्रतिशत से अधिक और सुसंगत वर्ष और सुसंगत वर्ष का ठीक पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्षों में तदर्थ पारिश्रमिक का कुल योग कम तीन वर्षों में आवेय प्रीमियम के कुल 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो उसकी सेवाएं नियम 8 के अनुसार समाप्त की जा सकेंगी।

8—कुछ मामलों में सेवा की समाप्ति :

(1) जहाँ कोई विकास अधिकारी व्यय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहा है और जहाँ ऐसी सीमा का अनुपालन करने का नियम 7 के उपबंधों के अधीन कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सका था वहाँ जोन प्रबंधक तीन मास की सूचना या उसके बदले में बेतन देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है :

परन्तु विकास अधिकारी को उसकी प्रस्तावित सेवा-समाप्ति के विरुद्ध कारण बताते का अवसर दिया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन पारित आवेय के विरुद्ध अपील, प्रबंध निदेशक को की जाएगी और कर्मचारिवृत्त नियमों के नियम 41, 42, 43, 44 और 45 के उपबंध, जहाँ तक हो सके, वहाँ तक ऐसी अपील को लागू होंगे।

(3) उपनियम (2) के अधीन अपील की जाने पर, प्रबंध निदेशक मामले के अभिनेय पर विचार करके और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुणगुण के आधार पर आवेय पारित कर सकेगा।

9. अवधेयता का आस्थापन :

(1) "कोई वेतन वृद्धि नहीं" से निम्न अवधेयता सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सुसंगत देय तारीख" कहा गया है) से अधिनिर्णीत नहीं की जाएगी किन्तु अनुवर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तक आस्थायित रखी जाएगी, यदि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई विकास अधिकारी, जिसने कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, ऐसी विहित व्यय सीमा पार कर चुका है, जिससे अवधेयता-सारणी के अनुसार अवधेयता दिया जाना आवश्यक हो जाता है :

परन्तु यह तब जब कि ऐसे सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों से अनुवर्तन निरंतर अवधेयता विहित व्यय सीमा पार नहीं की है या, जहाँ उसने पांच वर्षों की सेवा पूरी नहीं की है किन्तु कम से कम तीन वर्षों की सेवा पूरी कर चुका है और उसने विकास अधिकारी के रूप में पद का कार्य पार संभालने की तारीख से किसी वर्ष में विहित व्यय सीमा पार नहीं की है।

(2) जहाँ विकास अधिकारी उस नियम (1) में निर्दिष्ट अनुवर्ती वर्ष में विहित सीमा का अनुपालन करता है वहाँ ऐसी अवधेयताओं को जो आस्थायित रखी गई हैं, अधिनिर्णीत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और यदि कोई वेतन वृद्धि जो सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को उसे प्रत्यक्ष प्रयोज्य हो गई होती, अवधेयता के रूप में अनुज्ञात की गई थी तो ऐसी वेतन वृद्धि सुसंगत देय तारीख से निर्धारित कर दी जाएगी।

(3) जहाँ विकास अधिकारी किसी ऐसे अनुवर्ती वर्ष में विहित व्यय सीमा को पार कर चुका है वहाँ ऐसी अवधेयता जो आस्थायित रखी गई है, सुसंगत देय तारीख से अधिनिर्णीत कर दी जाएगी और ऐसे अनुवर्ती वर्ष में उसको संवत् अवधेयता पारिश्रमिक की समुचित वसूली प्राप्ति वर्ष के उसके वेतन में से की जाएगी और "कोई वेतन वृद्धि नहीं" की अवधेयता यदि कोई हो, अंतिम हो जाएगी और वह ऐसे अनुवर्ती वर्ष में विहित व्यय सीमा का अनुपालन करने में अपनी असफलता के लिए अवधेयता सारणी के अनुसार कार्रवाई किए जाने का भी दायी हो जाएगा।

(4) जहाँ अवधेयताओं को उपनियम (2) के अनुसार प्रवर्तित नहीं किया जाता है या वेतन वृद्धि सुसंगत देय तारीख से निर्धारित की जाती है वहाँ उपनियम (1) के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष को, यथास्थिति, पांच वर्ष या तीन वर्षों की निरंतर सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए उस वर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसमें उसने विहित व्यय सीमा पार नहीं की है।

(5) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई विकास अधिकारी ऐसे प्रक्रम पर है जहाँ दक्षता रोध हो वहाँ उस दक्षता रोध से परे उसे कोई वेतन वृद्धि मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि उसने नियम 10 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है।

10. दक्षता रोध :

(1) जहाँ किसी वेतनमान में दक्षता रोध है वहाँ विकास अधिकारी 1 अप्रैल 1988 को या उसके पश्चात् तब तक रोध के प्रागे वेतन वृद्धि पाने का योग्य प्रमाणित नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख (जिसे इस उपनियम में इसके पश्चात् "सुसंगत वर्ष" कहा गया है) के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में उसके वार्षिक पारिश्रमिक के प्रति निर्देश से उसका लागत अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक नहीं था, और

(ख) उसने सुसंगत वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्षों में उसको लागू व्यय सीमा पार नहीं की है।

(2) जहाँ किसी विकास अधिकारी को ऐसा दक्षता रोध पार करने के लिए पार करने से उसे पहले रोक दिया गया था, अनुज्ञा दी जाती है तो उसे भतलभी तारीख से केवल एक वेतन वृद्धि का अनुज्ञा दी जाएगी :

परन्तु दक्षता रोध के हटा दिए जाने पर एक से अधिक वेतन वृद्धि केवल तब अनुज्ञात की जा सकेंगी जब वह नियम 11, 12, 13 या 14 के अनुसार किसी वेतन वृद्धि के लिए प्राप्त हो जाता है।

(3) जहाँ किसी विकास अधिकारी ने दक्षता रोध पार कर लिया है किन्तु उसे किसी कारणवश वहाँ जो भी हो दक्षता रोध से न बचे कर दिया गया है वहाँ उसे उस दक्षता रोध को पार करने के अनुज्ञा केवल सब ई जा सकेंगी जब वह अपने अवधि वेतन वृद्धि के लिए प्राप्त हो जाता है जब तक कि उस वेतन वृद्धि का कारिग्य नियमों के नियम 39 के अधिन किसी अनुज्ञासुनात्मक अध्ययन के रूप में रोक नहीं गई है।

11. 31-3-88 को या उसके पूर्व पढ़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख के पूर्व कारिग्य नियमों की अनुसूची 3 के अनुसरण में मूल वेतन में कटौती का मूलतः प्रत्यावर्तन

(1) जहाँ किसी विकास अधिकारी ने इस नियम में निर्दिष्ट रीति में 1 अप्रैल 1988 के पूर्व पढ़ने वाली मूल्य निर्धारण तारीख के लिए सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्षों में व्यय सीमा का अनुपालन किया है और वह तत्पश्चात् व्यय सीमा का अनुपालन करना जारी रखता है वहाँ 20 जून, 1979 के पश्चात् उसके मूल वेतन में इस आधार पर की गई कटौती कि उसने किसी ऐसे मूल्य निर्धारण वर्ष में जिसकी शुरुआत सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख 31 मार्च, 1988 को या उसके पूर्व पढ़ने वाली थी, व्यय सीमा पार कर चुका है (मूल वेतन में ऐसी कटौती को इसमें इसके पश्चात् "पिछले वेतनहास" कहा गया है) उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार प्रत्यावर्तित की जा सकेंगी :

परन्तु यह तब जब कि जहाँ कोई विकास अधिकारी पिछली वेतनहास के प्रत्यावर्तन के लिए माँहत हो जाता है वहाँ पिछला वेतनहास जो 20 जून, 1979 के पश्चात् वाली मूल्य निर्धारण तारीख को पढ़ने वाले मूल्य निर्धारण के फलस्वरूप पहली बार किया गया था, प्रथमतः प्रत्यावर्तित किया जाएगा, पिछला वेतनहास जो तत्पश्चात् किया गया था अगली बार प्रत्यावर्तित किया जाएगा और आगे भी इस प्रकार किया जाता रहेगा।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए किसी वर्ष से संबंधित पिछला वेतनहास में वेतनमान में का एक प्रक्रम या एक से अधिक प्रक्रम सम्मिलित होंगे।

(2) इस नियम का फायदा विकास अधिकारी को केवल तब प्रयोज्य होगा जब उसने 1 अप्रैल 1987 को या उसके पश्चात् पढ़ने वाली मूल्य निर्धारण तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में किन्तु 1 अप्रैल 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "केन्द्रीय वर्ष" कहा गया है) और केन्द्रीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो निर्धारण वर्षों में व्यय सीमा का अनुपालन किया है और वह इस नियम के फायदे के लिए तब तक पात्र बना रहेगा जब तक वह केन्द्रीय वर्ष के ठीक प्रागामी अनुवर्ती मूल्य निर्धारण वर्षों व्यय सीमा का अनुपालन करता है और यदि किसी मूल्य निर्धारण वर्ष में द्वारा जिसमें वह व्यय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह अखला विच्छिन्न हो जाती है तो वह ऐसे मूल्य निर्धारण वर्ष से सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को या उसके पश्चात् इस नियम के अधीन फायदा प्राप्त करना बंद कर देगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, "श्रृंखला" से ऐसी तीन या अधिक अविच्छिन्न मूल्य निर्धारण वर्षों की श्रृंखला अभिप्रेत है जिसमें विकास अधिकारी ने व्यय सीमा पार नहीं की है :

परन्तु केन्द्रीय वर्ष की ठीक प्रागामी मूल्य निर्धारण वर्ष या उसके पश्चात् किसी मूल्य निर्धारण वर्ष की संगणना उन अनुवर्ती मूल्य निर्धारण वर्षों के प्रयोजनों के लिए केवल तब की जा सकेंगी जब ऐसे अनुवर्ती वर्ष में विकास अधिकारी का लागत अनुपात व्यय सीमा के दो प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(3) उपनियम (4) और उपनियम (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए :—

(i) जहाँ कोई विकास अधिकारी केन्द्रीय धर्म में 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् पड़ने वाली पहली मूल्य निर्धारण तारीख को व्यय सीमा का अनुपालन करता है और उसे तीन वर्ष की किसी सम्मिलित श्रृंखला का श्रेय प्राप्त है वहाँ एक वर्ष से संबंधित पिछले वेतनह्रास ऐसे प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष की तारीख से प्रत्यावर्तित किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विकास अधिकारी के संबंध में तीन वर्ष की सम्मिलित श्रृंखला से उस केन्द्रीय धर्म और वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें उस ने व्यय सीमा का अनुपालन किया है।

(ii) यदि, तीन वर्ष की किसी सम्मिलित श्रृंखला के अतिरिक्त किसी विकास अधिकारी का तीन वर्ष की गत श्रृंखला का एक ऐसी गत श्रृंखला से अधिक का श्रेय प्राप्त है तो उत्तरी वर्षों से जितनी तीन वर्ष की निरन्तर श्रृंखलाएँ हैं संबंधित पिछले वेतन ह्रास खंड (i) में निर्दिष्ट प्रथम मूल्य निर्धारण तारीख से प्रत्यावर्तित किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए किसी विकास अधिकारी के संबंध में 'तीन वर्ष की गत श्रृंखला से केन्द्रीय धर्म की ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष और ऐसे श्रृंखलाबद्ध मूल्य निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती अन्य अविच्छिन्न मूल्य निर्धारण वर्ष अभिप्रेत हैं जिनमें किसी विकास अधिकारी ने व्यय सीमा का अनुपालन किया है।

(iii) यदि विकास अधिकारी को तीन वर्ष की सम्मिलित श्रृंखला प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है किन्तु तीन वर्ष की गत श्रृंखला या ऐसी गत श्रृंखलाओं की अपेक्षित संख्या के अभाव में पिछले वेतनह्रास प्रत्यावर्तित नहीं किए जा सकते, और यदि केन्द्रीय धर्म के ठीक आगामी मूल्य निर्धारण वर्ष से संबंधित सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को उसके नाम में विशेष श्रृंखला प्रोव्हीन जाती है तो आदेश पिछले वेतनह्रास यदि कोई हो, ऐसी सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से इस धर्म के अधीन रहते हुए प्रत्यावर्तित किए जा सकेंगे। कि जहाँ एक वर्ष से संबंधित मूल वेतन में कमी के अंतर्गत वेतनमान में एक से अधिक प्रक्रम सम्मिलित हैं वहाँ आदेश पिछले वेतनह्रास का कोई प्रत्यावर्तन तब तक देय नहीं होगा जब तक कि भावी लागत से वेतनमान में कम से कम एक प्रक्रम को समर्थन प्राप्त नहीं होता किन्तु विकास अधिकारी उस वर्ष से संबंधित मूल वेतन में कमी के शेष प्रक्रम के प्रत्यावर्तन के लिए भगले अवसर पर अर्हित हो सके और ऐसे अवसर पर ऐसे शेष प्रक्रमों का एक वर्ष से संबंधित मूल वेतन में कमी समाप्त जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए :—

(क) किसी विकास अधिकारी के संबंध में "श्रृंखला वेतन" से केन्द्रीय धर्म और उस केन्द्रीय धर्म के ठीक पूर्ववर्ती और अनुवर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष जिनमें विकास अधिकारी ने व्यय सीमा का अनुपालन किया है ;

(ख) "आदेश पिछले वेतनह्रास" से एक वर्ष में एक या अधिक प्रक्रमों तक मूल वेतन में की गई कमी अभिप्रेत है जो या जिसका भाग यदि प्रत्यावर्तित किया गया तो उससे भावी लागत अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहेगा ;

(ग) "भावी लागत" से वह अनुपात अभिप्रेत है जो सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख (जिसके अंतर्गत उस तारीख को और उससे सभी वेतन वृद्धियाँ और प्रस्तावित प्रत्यावर्तन भी हैं) को किसी विकास अधिकारी को लागू वार्षिक पारिश्रमिक का पूर्ववर्ती वर्ष की आदेश प्रीमियम से है और भावी लागत अधिकतम सीमा के अंतर्गत तब सभी जाएगी जब किसी विकास अधिकारी को लागू ऐसा वार्षिक पारिश्रमिक ऐसे आदेश प्रीमियम को उसकी व्यय-सीमा के प्रतिपात से अधिक नहीं है।

(घ) "प्रत्यावर्तन" से पहले वेतनह्रास का प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो)।

(iv) यदि खंड (i) से खंड (iii) के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् कोई पिछले वेतनह्रास प्रत्यावर्तित किए जाने योग्य है दो तीन वर्ष की सुसंगत श्रृंखला के लिए अतिरिक्त आदेश पिछले वेतनह्रास प्रत्येक ऐसी संबंधित मूल्य निर्धारण तारीख से जिन को वह अपने नाम से अग्रगतिशील श्रृंखला अर्जित करता है, प्रत्यावर्तित किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए :—

(क) कलेंडर वर्ष से प्रारंभ होने वाली किसी श्रृंखला के संबंध में, "अग्रगतिशील श्रृंखला" सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से उस केन्द्रीय धर्म के प्रारंभ तक जिसमें विकास अधिकारी ने व्यय सीमा का पालन किया है, पीछे संगठित तीन वर्ष की श्रृंखला अभिप्रेत है।

(ख) 'तीन वर्ष की सुसंगत श्रृंखला' से सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की श्रृंखला अभिप्रेत है केवल जिसका उस तारीख को आदेश पिछले वेतनह्रास के प्रत्यावर्तन के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा।

(4) यदि विकास अधिकारी वेतनमान में ऐसे प्रक्रम पर है, जहाँ कोई दशता-रोध हो वहाँ कोई प्रत्यावर्तन तब तक अनुपात नहीं होगा जब तक कि वह उस मूल्य निर्धारण तारीख के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में जिसको वह अवस्था प्रत्यावर्तन के लिए अर्हित हो सके, नियम 10 के अनुसार दशता-रोध पार करने के लिए पात्र नहीं हो जाता है।

(5) कोई प्रत्यावर्तन अनुपात नहीं होगा यदि, प्रत्यावर्तन पर, विकास अधिकारी वेतनमान में किसी ऐसे प्रक्रम पर पहुँच जाएगा जिस पर वह इस आधार पर नहीं पहुँच पाता कि उसने व्यय सीमा पार की थी और ऐसी दशा में प्रत्यावर्तन वेतनमान में उस प्रक्रम तक सीमित होगा जिस पर वह सामान्य रूप से पहुँच पाता।

12. 31-3-1988 को या उसके पूर्व पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख के पूर्व कर्मचारिवृत्त नियमों की अनुसूची 3 के अनुसरण में मूल वेतन में की गई कमी का भावी प्रत्यावर्तन—अनुकूली रीति :

(1) नियम 11 के उपनियम (4) और उपनियम (5) के अधीन रहते हुए, यदि किसी विकास अधिकारी का लागत अनुपात 1 अप्रैल, 1989 को या उसके पश्चात् किन्तु 31 मार्च, 1992 के पूर्व पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीखों के पूर्ववर्ती प्रथम, द्वितीय या तृतीय मूल्य निर्धारण वर्ष में 15% से अधिक नहीं है तो 31 मार्च, 1988 को या उसके पूर्व पड़ने वाली मूल्य निर्धारण तारीखों के संबंध में एक या अधिक वर्षों से संबंधित पिछले वेतनह्रास नियम 11 के उपनियम (1) के परन्तुक में त्रिनिश्रिष्ट रीति में, सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीखों से, उम विस्तार तक जिन तक भावी लागत अधिकतम सीमा तक रहती है, प्रत्यावर्तित किए जा सकेंगे।

परन्तु यदि विकास अधिकारी नियम 11 के अनुसार किसी प्रत्यावर्तन के लिए भी पात्र है तो वह उस नियम या इस नियम के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए अपराधिकार्य दे सहाय।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "पिछले वेतनह्रास," "प्रत्यावर्तन" और "भावी लागत" पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके नियम 11 में हैं।

13. जहाँ सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख 1-4-1988 को या उसके पश्चात् पड़ती है, वहाँ मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप अवधेयता—सारणी के अनुसार मूल वेतन में की गई कमी का पुनः स्थापन

(1) 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप किसी विकास अधिकारी के मूल वेतन में की गई कमी (जिसे हमें इसके पश्चात् "मूल वेतनह्रास" कहा गया है)

को इस नियम या नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पुनः स्थापित किया जा सकेगा।

- (2) जहाँ कोई विकास अधिकारी इस नियमों के अनुसार पुनः स्थापन के लिए अर्हित करता है वहाँ मूल वेतन में कमी जो पहली बार 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् की गई थी, प्रथमतः पुनः स्थापन की जाएगी; मूल वेतन में कमी जो तत्पश्चात् की गई थी, अगली बार पुनः स्थापन की जाएगी और इस प्रकार की जाती रहेगी।

परन्तु यदि कोई विकास अधिकारी उस मूल्य निर्धारण तारीख के जिससे उसके मूल वेतन में कमी की गई थी, आगामी पांच मूल्य निर्धारण वर्षों के भीतर पुनः स्थापन के लिए अर्हित होने में असफल रहता है तो उस कमी का कोई पुनः स्थापन नहीं किया जाएगा और उस वर्षा में कुल मूल वेतन में अगली कमी, यदि कोई हो, पुनः स्थापन के लिए वेतन माननी जाएगी यदि वह बाद में पुनः स्थापन के लिए अर्हित हो जाता है।

परन्तु यह और कि इस नियम और नियम 14 के अधीन मूल वेतन में कमी का पुनः स्थापन विकास अधिकारी के रूप में पूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल तीन अवसरों तक सीमित रहेगा।

(3) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि 1 अप्रैल 1988 को या उसके पश्चात् पढ़ने वाली किसी सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को मूल्य निर्धारण तारीख से यह प्रकट होता है कि किसी विकास अधिकारी ने पूर्ववर्ती वर्ष में व्यय सीमा पार नहीं की है और यह कि ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष और अगले दो पूर्ववर्ती वर्षों में लागत अनुपात कुल मिलाकर उन तीन वर्षों के लिए (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तीन वर्ष का ब्लाक कहा गया है) सम्मिलित व्यय सीमा से अधिक नहीं है तो आदेश चालू वेतनहान सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से पुनः स्थापित किया जाएगा।

परन्तु किसी पूर्ववर्ती वर्ष में विकास अधिकारी व्यय सीमा का अनुपालन नहीं करता है तो वह पुनः स्थापन के लिए तब अर्हित हो सकेगा जब किसी पञ्चाव्वर्ती सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को तीन वर्षों का ब्लाक हो,

परन्तु यह और कि एक वर्ष से अधिक में संबंधित चालू वेतनहान का एक सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को पुनः स्थापन किया जाएगा भले ही भावी लागत एक वर्ष में अधिक वेतनहान के पुनः स्थापन का समर्थन करे।

स्पष्टीकरण —उस नियम के प्रयोजनों के लिए—

- (1) "तीन वर्ष का ब्लाक" से अभिप्रेत है ऐसा प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें विकास अधिकारी ने व्यय सीमा पार नहीं की है और अगले दो पूर्ववर्ती वर्षों ;
- (2) "आदेश चालू वेतनहान" में एक वर्ष से संबंधित चालू वेतन हान अभिप्रेत है जो यदि पुनः स्थापित किया गया, तो फिर भी भावी लागत को अधिकतम सीमा के अन्तर्गत रखेगा ;
- (3) "भावी लागत" से वह अनुपात अभिप्रेत है जो सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख (जिसके अन्तर्गत उस तारीख को और से मूल वेतन बढ़िया और प्रस्तावित पुनः स्थापन भी है) को किसी विकास अधिकारी को लागू वार्षिक पारिश्रमिक या पूर्ववर्ती वर्ष की आदेश प्रीमियम से है और भावी लागत को अधिकतम सीमा के अन्तर्गत समझा जाएगा यदि किसी विकास अधिकारी को लागू ऐसा पारिश्रमिक ऐसे आदेश प्रीमियम के उनके व्यय सीमा के प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(4) नियम 11 के उपनियम (4) और उपनियम (5) के उपबंध, जहाँ तक हो सके, वेतन में कमी के पुनः स्थापन को वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे ऐसी कमी के प्रत्यावर्तन को लागू होते हैं।

14. जहाँ सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख 1-4-1988 को या उसके पश्चात् पढ़ती है वहाँ मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप अवप्रेरणा-सारणी के अनुसार मूल वेतन में की गई कमी का पुनः स्थापन—अनुकाली रीति:—

नियम 13 के उपनियम (2) और उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई विकास अधिकारी तीन क्रमवर्ती मूल्य निर्धारण वर्षों में व्यय सीमा पार नहीं करता है तो एक वर्ष से संबंधित चालू वेतन हान ऐसे पिछले मूल्य निर्धारण वर्ष की ठीक आगामी सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से पुनः स्थापित किया जा सकेगा।

15. भविष्य निधि

(1) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम 1986 के नियम 8 में किसी बात के होने हुए भी, जहाँ नियम 11, 12, 13 या 14 में संश्लिष्ट उपबंधों के अनुसार सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से किसी विकास अधिकारी को पिछले वेतनहान या चालू वेतनहान प्रत्यावर्तित या पुनः स्थापित किए जाते हैं। वहाँ निगम अपने द्वारा स्थापित भविष्य निधि में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निधि" कहा गया है) में उस अवधि के संबंध में जिसके लिए ऐसे वेतनहान प्रत्यावर्तित या पुनः स्थापित किए गए हैं, ऐसे वेतनहानों में समाविष्ट मूल वेतन के कुल योग का 8% प्रतिशत की अधिकतम रकम का अभिदाय करेगा।

परन्तु यदि उस अवधि के दौरान या उस अवधि के किसी भाग के दौरान जिसमें उक्त वेतनहान प्रयुक्त थे वह दर जिस पर नियोजक का अभिदाय 8% प्रतिशत से अधिक था तो निगम सुसंगत अवधि से संबंधित मूल वेतन के उस भाग में ऐसी अधिक दर पर अभिदाय कर सकेगा।

परन्तु यह और कि विकास अधिकारी निधि में निगम से अपेक्षित अभिदायों के बग़ैर रकम का निधि के निम्नों के अनुसार और उस रीति में जिसका उसे निगम द्वारा निदेश दिया गया हो, अपने प्रतिरिक्त अभिदाय के रूप में अभिदाय करेगा।

(2) निगम निधि में तब और उस विस्तार तक जिस तक विकास अधिकारी उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन ऐसे प्रतिरिक्त अभिदाय करता है, अभिदाय करेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन निगम द्वारा किए गए अभिदाय किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे जिसके लिए नियोजक के अभिदाय निधि के नियमों के अधीन उपलब्ध नहीं हैं।

(4) इस नियम की कोई बात ऐसे किसी विकास अधिकारी को लागू नहीं होगी जो निगम द्वारा अनुमोदित किसी अधिवाधिकी निधि में अभिदाय कर रहा है।

16. विशेष मामलें :

(1) प्रबंध निदेशक किसी मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा और मामलों के गुणागुण को ध्यान में रखते हुए विकास अधिकारी को अनुतोष मंजूर कर सकेगा, यदि विकास अधिकारी केन्द्रीय वर्ष में व्यय-सीमा का अनुपालन करने में कठिन प्रयत्न प्रदर्शना के कारण नियम 11 के फायदे का महार नही है।

परन्तु यह तब जबकि वह अनुपात जो केन्द्रीय वर्ष और ठीक पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्षों के लिए वार्षिक पारिश्रमिक के कुल योग का उन वर्षों में आदेश प्रीमियम के कुल योग से है, व्यय सीमा से अधिक नहीं है ;

परन्तु यह और कि ऐसा कोई अनुतोष ऐसे किसी फायदे से अधिक नहीं होगा कि विकास अधिकारी को तब तक उपलब्ध होता जब वह नियम 11 के अधीन स्वयं को अर्हित कर लेता।

(2) प्रबंध निदेशक, जो प्रबंधक की मिकारिष पर, अवप्रेरणा सारणी के अनुसार मूल वेतन में कमी की तारीख के पश्चात् किसी विकास अधिकारी के किसी मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा यदि वह

नियम 13 या नियम 14 के अधीन पुनः स्थापन के लिए ग्रहित नहीं करता है और मामले के गुणागुण को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमोद प्रदान कर सकेगा किन्तु उस अनुमोद से अधिक नहीं होगा जो उसे तब अनुमोद होता जब वह पुनः स्थापन के लिए उक्त नियमों में से किसी के अधीन स्वयं को ग्रहित करता ।

17. प्रेरणा :

निगम द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन प्रेरणा बोनस किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी को तब मंजूर की जा सकेगी जब उस वर्ष में उसके वार्षिक पारिश्रमिक के प्रति निर्वेश से लागत अनुपात उस वर्ष के आदेय प्रीमियम के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

18. विकास अधिकारी की प्रोत्ति :

योग्य समझे जाने वाले किसी भी विकास अधिकारी की प्रोत्ति कर्मचारिवृन्द नियमों के नियम 7 के अनुसार सहायक शाखा प्रबंधक या सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में की जा सकती है ।

19. सेवा-समाप्त विकास अधिकारी की पुनर्नियुक्ति :

यदि किसी ऐसे विकास अधिकारी ने जिसकी सेवाओं को नियम 8 के अनुसरेण में समाप्त किया गया है, ऐसी सेवा समाप्ति की तारीख को वर्ष-2 में कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 55 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो वह ऐसी ग्रहता और योग्यता के अनुसार जो अधि नियम की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन प्रिनि-विष्ट की जाए, वर्ष-3 में प्रशासनिक कार्य करने के लिए सहायक या अधिलेख लिपिक के रूप में नियम की सेवा में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

पत्र सेवा समाप्ति के परिणामस्वरूप सेवा में व्यवधान के होते हुए भी नियम में उसकी सेवा छुट्टी के प्रयोजन के लिए निरन्तर मानी जाएगी और उपदान या भविष्य निधि के प्रयोजन के लिए भी यदि उसने वह प्राप्त नहीं की है और यदि उसने प्राप्त की है किन्तु वह निगम को उपदान या भविष्य निधि की ऐसी रकम का सदाय करता है जो उसने प्राप्त की है ।

20. निरसन और व्याप्ति

(1) कर्मचारिवृन्द नियम की अनुसूची 3 और जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तों का परिवर्तन) आदेश, 1978 ऐसी बातों के सिवाए निरसित किया जाता है जो कर्मचारिवृन्द नियम की अनुसूची 3 के अधीन की गई है या किए जाने से लोप की गई है और जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (पारिश्रमिक और सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तों का परिवर्तन) आदेश, 1978 भी निरसित किया जाता है ।

(2) इन नियमों की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह कर्मचारिवृन्द नियमों के अनुसार किसी विकास अधिकारी को सेवाभ्युक्त करने, सेवानिवृत्त करने या उसकी सेवाओं को अवधारित करने के संक्रम प्राधिकारी के अधिकार पर प्रभाव डालता है या कर्मचारिवृन्द नियमों के नियम 39 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट किन्ही आधारों पर उस पर कोई शास्ति अधिरोपित करने के अनुश्रान्तिक प्राधिकारी के अधिकार को प्रभावित करती है या ऐसे मामलों की बाबत जो इन नियमों में उल्लिखित नहीं हैं विकास अधिकारियों के कर्मचारिवृन्द नियमों पर लागू होती है ।

21. निर्बंधन

जहां इन नियमों के निर्बंधन की बाबत कोई संदेह या कठिनाई पैदा होती है वहां वह विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देशित की जाएगी ।

[फा. सं. 2(60)/बीमा. III/86]

एन. आर. रंगनाथन, अपर सचिव

राष्ट्रीयकरण टिप्पण :

केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 1988 से भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की सेवा के कुछ निबंधों और शर्तों को पुनरीक्षित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है । तदनुसार नियमों को 1 अप्रैल 1988 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 1989

INSURANCE

Life Insurance Corporation of India
(Department of Economic Affairs)
Terms and Conditions of
Service) Rules, 1989.

G.S.R. 643(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (cc) of sub-section (2), of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules regulating certain terms and conditions of service relating to business performance of Development Officers of the Life Insurance Corporation of India, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1988.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Act" means the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) ;
- (b) "ad hoc annual remuneration" means the yearly remuneration applicable to a Development Officer for the purpose of disincentives, computed in the manner set forth in clause (i) of the Explanation to sub-rule (1) of rule 7 ;
- (c) "annual remuneration" means the basic pay, special pay, personal pay, dearness allowance, and all other allowances and non-profit sharing or ex-gratia bonus due to or paid to, a Development Officer during the appraisal year and includes the expenses payable or reimbursed to him or incurred by the Corporation during that year in respect of travelling, residential telephone and insurance premium and taxes on motor vehicles, but does not include incentive bonus and additional conveyance allowance paid to him in accordance with rules 17 ;

(d) "appraisal date" means—

(I) in relation to a Development Officer appointed on or after the 1st day of April, 1988,

(A) in the first year of his service the first day of the month following that in which he completes twelve months of service from the date of his appointment; and

(B) in every subsequent year of his service, the first day of the month following that in which he completes twelve months of service from the last appraisal date;

(II) in relation to a Development Officer appointed prior to the 1st day of April, 1988,

(A) in the first year of his service from 1st April, 1988,—

(i) 1st April, 1988 if he has completed twelve months of service as on 31st March, 1988; or

(ii) the 1st day of the month following that in which he completes a further period of twelve months of service from the date on which his last annual increment accrued (whether released or not) in accordance with sub-rule (2) of rule 50 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, if he had completed twelve months of service or more prior to 1st March, 1988; and

(B) in every subsequent year of service, the first day of month following that in which he completes twelve months of service from the last appraisal date;

(e) "appraisal year" means the period between two consecutive appraisal dates; and the period of twelve months of service preceding the appraisal date ascertained in accordance with item (A) of sub-clause (I), and each period of twelve months of service next preceding the appraisal date ascertained in accordance with item (A) of sub-clause (II) of clause (d), shall also be an appraisal year;

(f) "cost ratio" in relation to a Development Officer means the ratio which his annual remuneration in any year, or his ad hoc annual remuneration, if applicable, bears to the eligible premium of that year and expressed as a percentage of such eligible premium;

(g) "decrement" means reduction in basic pay by one or more stages in the scale of pay on one or more occasions;

(h) "Development Officer" means a whole-time salaried employee of the Corporation belonging to Class II appointed as Development Officer and includes any person

who became an employee of the Corporation on the 1st day of September, 1956 and is working as a Development Officer;

(i) "disincentive" means reduction in conveyance allowance or non-grant of increment or decrement as provided in the "Table of Disincentives";

(j) "eligible premium" means such proportion as may be specified by the Corporation from time to time of the first year's premiums received by the Corporation in respect of the business secured by the agents in the organisation of a Development Officer which is adjusted in the relevant appraisal year;

(k) "expense limit" in respect of an appraisal year in relation to a Development Officer working in an operational area specified in column (1) of the Table below (hereinafter referred to as the "Table of Expense Limit") means the percentage of the eligible premium of that year as specified in the corresponding entry in column (2) thereof :—

TABLE OF EXPENSE LIMIT

If the Development Officer is working in operational area	Percentage of the eligible premium
(1)	(2)
A	22%
B	23%
C	24%
D	25%
E	26%

Note : The expense limit of a Development Officer for any appraisal year is expressed as a percentage of the eligible premium of that year; a Development Officer is said to exceed the expense limit if his annual remuneration in that year is in excess of the expense limit; such excess or the ratio which such annual remuneration bears to the eligible premium of that year may also be expressed as a percentage of the eligible premium;

(l) "operational area" with reference to a Development Officer means the area in which he is posted to work as such Development Officer and a Development Officer is said to be working in operational area—

'A' if he is working in a City, Urban agglomeration or Town with an ascertained population of more than 10 lakhs;

'B' if he is working in a City, Urban agglomeration or Town with an ascertained population of 4 lakhs or above but not more than 10 lakhs;

'C' if he is working in a City, Urban agglomeration or Town (not being a rural area or a deep rural area) with an ascertained population of less than 4 lakhs;

'D' if he is working in a rural area; and

'E' if he is working in a deep rural area or any hilly area specified in Explanation (4) or any other hilly area which the Central Government may in consultation with the Corporation by notification in the Official Gazette specify in this behalf.

Explanation : For the purposes of this clause,—

- (1) "ascertained population" means the population as ascertained from the latest Census Report of the Government of India;
- (2) a Development Officer is said to be working in a "rural area" if his headquarters is at a place with an ascertained population of 30,000 or less and his operational area has an ascertained population of not more than one lakh;
- (3) a Development Officer is said to be working in a "deep rural area" if his headquarters is at a place with an ascertained population of 10,000 or less and his operational area has an ascertained population of not more than 60,000;
- (4) a Development Officer is said to be working in a "hilly area" if his headquarter is at a place situated at a height of 1000 metres and over, above mean sea level, with an ascertained population of 20,000 or less and his operational area has an ascertained population of not more than 75,000;
- (m) "preceding year" or "relevant appraisal year" means the appraisal year immediately preceding the relevant appraisal date;
- (n) "prescribed expense limit" or "prescribed cost ratio" means the increased expense limit ascertained in accordance with proviso to sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 4, where such expense limit is applicable to a Development Officer, or if it is not so applicable to him, the expressions shall mean the expense limit applicable to him;
- (o) "relevant appraisal date" means the appraisal date on which the performance of the Development Officer for the appraisal year immediately preceding that date is assessed for any purpose under these rules or was assessed hitherto under the staff rules;
- (p) "service" means the period spent on duty as a Development Officer and leave including extraordinary leave which has been condoned under Rule 69(4) of staff rules;
- (q) "staff rules" means the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960;
- (r) "succeeding year" means the period of twelve months commencing from the relevant appraisal date;

(s) "Table of Disincentives" means the Table below sub-rule (1) of rule 7;

(t) "Table of Increased Expense Limit" means the Table below sub-rule (2) of rule 4;

(u) words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the staff rules shall have the meanings assigned to them in the staff rules.

3. Tenure :

Subject to the provisions of these rules, a Development Officer shall hold office by the same tenure and in the same manner as any other class of employee in the Corporation.

Provided that he shall conform to the expense limit applicable to him:

Provided further that the services of a confirmed Development Officer shall not be terminated on the ground of poor business production resulting in cost ratio in excess of the expense limit applicable to him, unless he has been given an opportunity to conform to the expense limit as provided in rule 7.

4. Expense limit applicable to Development Officers :

(1) The expense limit applicable to a Development Officer shall be as specified in the Table of Expense Limit :

Provided that where a Development Officer has put in more than ten years of service as a Development Officer at the Commencement of the relevant appraisal year, the expense limit applicable to him for the relevant appraisal year shall be the expense limit applicable to his operational area as increased by one percent, if, at or before such commencement of the relevant appraisal year, he has completed 50 years of age and such expense limit shall be increased by two percent if he has completed 52 years of age by three percent, if he has completed 54 years of age with effect from the 1st day of October, 1987.

(2) Where the equitable relief granted to a Development Officer forms part of his annual remuneration in pursuance of the provisions contained in rule 10 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, the expense limit applicable to him for the appraisal years specified in column (1) of the Table below shall be the expense limit as increased with effect from the 1st day of October, 1987, by the percentage specified in the corresponding entry in column (2) thereof:

Table of Increased Expense Limit

Appraisal years commencing on the first day of any of the twelve months in the following blocks		Percentage
(1)	(2)	
(a) October, 1986—September, 1987		2%
(b) October, 1987—September, 1988		2%
(c) October, 1988—September, 1989		1%

(3) The increased expense limit specified in the proviso to sub-rule (1) and sub-rule (2) shall apply to appraisals due on the relevant appraisal date falling on or after 1st October, 1987 in respect of operational areas 'A', 'B', 'C' and 'D':

Provided that in respect of appraisals due on the relevant appraisal dates falling on or after 1st October, 1987 but before 1st April, 1988, the opportunity to conform to the expense limit shall be regulated in accordance with the Table below paragraph 5 in Schedule III of the staff rules as in force at the relevant time.

(4) The increased expense limit specified in the proviso to sub-rule (1) and sub-rule (2) shall apply to appraisals due on the relevant appraisal date falling on or after 1st April, 1988 in respect of operational area 'E'.

(5) Notwithstanding anything contained in the proviso to sub-rule (1) or sub-rule (2) the percentages specified in column (2) of the Table of Disincentives or the percentages specified in sub-rule (8) of rule 7 shall not be increased.

5. Increments :

(1) Increments shall ordinarily be drawn by a Development Officer as a matter of course in accordance with rule 56 of the staff rules, unless he has reached the maximum of the grade or the increment cannot be allowed in accordance with rule 7 or rule 10 or it is withheld as a disciplinary measure under rule 39 of the staff rules.

(2) Where no increment is granted to a Development Officer in any year in accordance with rule 7 as a disincentive, such increment shall not be granted to him in any subsequent year except in accordance with the provisions contained in rule 9.

6. Conveyance Allowance :

Every Development Officer shall be entitled to such conveyance allowance as may be granted by the Corporation from time to time:

Provided that the conveyance allowance admissible to a Development Officer in any year shall be subject to the provisions of rule 7

7. Opportunity to conform to the expense limit :

(1) Where the annual remuneration of any Development Officer in the preceding year or years is in excess of the expense limit, his services shall not be terminated merely on that ground if his case is capable of being dealt with by awarding disincentives, subject to the provisions of rule 9, from the relevant appraisal date as provided in the Table of Disincentives, so as to afford him opportunity to conform to the expense limit.

Provided that for the purpose of award of disincentives in accordance with the Table of Disincentives his performance shall be appraised with reference to the ad hoc annual remuneration and the prescribed;

TABLE OF DISINCENTIVES

Sl. No. Where ad hoc annual remuneration is in excess of the prescribed expense limit or cost ratio is in excess of prescribed limit.		Disincentives where the ad hoc annual remuneration is in excess of the prescribed expense limit or cost ratio is in excess of prescribed limit in the appraisal year next preceding the relevant appraisal date.				
		On the first occasion	On the second successive occasion	On the third successive occasion	On the fourth successive occasion	On the fifth successive occasion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(A)	By not more than 2% (provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 35%)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(2)	By more than 2% but not more than 6% (provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 35%)	30% cut in CA	50% cut in CA	60% cut in CA	60% cut in CA and no increment	80% cut in CA and no increment
(3)	By more than 6% but not more than 9% (provided the cost ratio in the appraisal year is not more than 35%)	50% cut in CA	60% cut in CA	60% cut in CA and no increment	80% cut in CA and no increment	80% cut in CA and no increment and one decrement
(4)	By more than 9% (provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 35%)	60% cut in CA	60% cut in CA and no increment	80% cut in CA and no increment	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement

1	2	3	4	5	6	7
(5) Where the cost ratio in the appraisal year is more than 35% but not more than 40%	60% cut in CA and no increment	60% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement
(6) Where the cost ratio in the appraisal year is more than 40%	60% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement	80% cut in CA and no increment and one decrement

Note: For the purposes of this Table:—

- (a) "cut in CA" means reduction in Conveyance Allowance;
- (b) "no increment" means non-grant of increment;
- (c) "decrement" means reduction in basic pay by one stage.

Explanation: For the purposes of this sub-rule,—

(i) (a) The ad hoc annual remuneration for the purpose of appraisal for award of disincentive shall be formally ascertained and shall be deemed to be twelve times of the basic pay, special pay, personal pay, separate pay, dearness allowance and all other allowances including conveyance allowance admissible to a Development Officer on the first day of the appraisal year preceding the relevant appraisal date and non-profit sharing or ex-gratia bonus due or paid to him during the appraisal year as also the total expenses payable or reimbursed to him or incurred on him or due in respect of travelling, residential telephone and insurance premium and taxes on motor vehicles:

Provided that if his conveyance allowance has been increased during the preceding year either as a consequence of his acquiring a vehicle or switching to a different type of vehicle or by reason of any revision of conveyance allowance, the increased conveyance allowance paid to him during the year shall be added to arrive at the ad hoc annual remuneration applicable to him.

(b) The method of computing the ad hoc annual remuneration in the foregoing manner shall govern all appraisals due on the relevant appraisal date falling on or after 1st April, 1988 for the purpose of disincentives:

Provided that for the appraisals due on the relevant appraisal dates which may fall on or after 1st April, 1989, if the ad hoc annual remuneration for the preceding year (hereafter in this sub-clause referred to as the "relevant year") computed in the manner specified in sub-clause (a) exceeds the ad hoc annual remuneration computed in the same manner for the appraisal year next preceding the relevant year by more than 10 per cent, the ad hoc annual remuneration for the relevant year shall be deemed to be 110% of the ad hoc annual remuneration computed in accordance with sub-clause (a) for such appraisal year next preceding the relevant year:

Provided further that if the conveyance allowance of the Development Officer has been increased during the relevant year either as a consequence of his acquiring a vehicle or switching over to a different

type of vehicle or by reason of any revision of conveyance allowance, the increased conveyance allowance paid to him during the year shall be added to the amount computed in accordance with the preceding proviso to arrive at his ad hoc annual remuneration.

(c) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) or sub-clause (b), where a Development Officer has put in more than ten years of service as a Development Officer and has completed 55 years of age at the commencement of the relevant appraisal year, his performance shall be appraised for the purpose of award of disincentives with reference to the annual remuneration applicable to him as formally ascertained for the appraisal year at the commencement of which he has fulfilled the requirements specified in this clause and such annual remuneration shall be deemed to be the ad hoc annual remuneration also in his case:

Provided that in respect of a Development Officer who had fulfilled the requirements as to the aforesaid service and age on a date prior to 1st April, 1988, or at or before the commencement of any appraisal year, the ad hoc annual remuneration shall be deemed to be the annual remuneration applicable to him as formally ascertained in the relevant appraisal year commencing on or after 1st October, 1986:

Provided further that if the conveyance allowance of the Development Officer has been increased in any subsequent year either as a consequence of his acquiring a vehicle or switching over to a different type of vehicle or by reason of any revision of conveyance allowance, the increased conveyance allowance paid to him shall be added to the amount computed in accordance with the preceding provisions to arrive at his ad hoc annual remuneration in such subsequent year and thereafter.

(d) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses, if the annual remuneration of Development Officer in any appraisal year was less than the ad hoc annual remuneration computed in the manner specified above, such annual remuneration shall be deemed to be the ad hoc annual remuneration applicable to him in that appraisal year for the purpose of appraisal for award of disincentives.

(e) Where the scales of pay or allowances are altered in pursuance of any rules relating to general revision of the terms and conditions of service of Development Officers, the computation of the ad hoc annual remuneration under the foregoing sub-clauses shall be subject to the provisions of such rules issued under Section 48 of the Act.

(f) The computation of ad hoc annual remuneration in term of this clause shall be for the purpose of disincentives only and for all other purposes the annual remuneration shall be taken into account.

(g) For the purposes of clause (i) of this Explanation: the remuneration shall be formally ascertained by calculating or computing the remuneration to which the employee is eligible under these rules in the normal course, without taking into account any deduction, reduction or withholding of any part of the remuneration under special circumstances, such as suspension, extraordinary leave or sick leave on half-pay, or for any other reasons.

(ii) The application of the Table of Disincentives shall be subject to the provisions contained in rule 9 provided the services of the Development Officer are not liable to be terminated under sub-rule (2) or sub-rule (8) of this rule.

(iii) For the purpose of the Table of Disincentives, the ad hoc annual remuneration of a Development Officer shall be deemed to be in excess of the prescribed expense limit on a successive occasion if such remuneration exceeds such expense limit in two consecutive appraisal years even though the excess percentage over the prescribed expense limit may vary and an appraisal year in which the Development Officer exceeds the prescribed expense limit even though there is no disincentive shall also be reckoned for ascertaining whether the expense limit is exceeded on successive occasions and the disincentive on the successive occasion shall correspond to the excess of the prescribed expense limit in the appraisal year next preceding the relevant appraisal date.

(iv) The Table of Disincentives shall be repeatedly applied, if, after conforming to the prescribed expense limit, the Development Officer exceeds it again at a later date.

(2) If, as a consequence of the application of the provisions contained in sub-rule (1) the basic pay arrived at falls below the minimum of the grade applicable to the Development Officer, his basic pay shall be fixed at such minimum :

Provided that the fixation of basic pay at minimum under this sub-rule shall not be allowed more than once during the entire service of a Development Officer and if, on a second occasion, the basic pay so arrived at falls below such minimum his services shall be liable to be terminated in accordance with rule 8.

(3) (a) Where the basic pay of a Development Officer is reduced or fixed under sub-rule (1) or sub-rule (2) (hereafter referred to as "revised basic pay") he shall be allowed only such allowances and other benefits as are admissible to him on that basic pay;

(b) Where his conveyance allowance has been reduced, he shall only be entitled to the conveyance allowance as so reduced on the basis of the revised basic pay:

Provided that there shall be no protection of the annual remuneration either by granting a personal allowance or otherwise; and no arrears of pay or any allowance for the past period consequent on his conforming to the expense limit later on shall be payable.

(4) The appointing authority shall be the competent authority for implementing the provisions of sub-rules (1), (2), (3) and it shall determine the matters specified in the said sub-rules, as soon as may be, after the expiry of the relevant appraisal year :

Provided that the competent authority concerned shall, before deciding any matter under this rule, give an opportunity to the Development Officer to make a representation.

(5) Where the representation received under proviso to sub-rule (4) discloses,—

(a) any actual inaccuracies in the computation of eligible premium or other figures, the competent authority shall revise his decision to the extent it is warranted by the revised figures and pass appropriate orders disposing of the representation;

(b) any cause beyond the control of the Development Officer, such as accident or sickness to justify relaxation of the expense limit and he pleads that the award of disincentives should not be effected on that ground, the competent authority shall forward the representation to the Zonal Manager, for decision.

(6) If the Zonal Manager is satisfied that there is any merit in the representation, he may consider the circumstances of the case and pass such orders as he may think fit.

(7) A Development Officer whose representation has been rejected by the Zonal Manager may submit a memorial to the Chairman in respect of that matter.

(8) Notwithstanding any thing contained in the foregoing provisions of this rule, where the ad-hoc annual remuneration of a Development Officer in any preceding year (hereafter in this sub-rule referred to as the "relevant year") exceeds 50 per cent of the eligible premium of that year and the aggregate of the ad hoc remuneration in the relevant year and the two appraisal years immediately preceding the relevant year exceeds 50 per cent of the aggregate of the eligible premium in those three years, his services shall be liable to be terminated in accordance with rule 8.

8. Termination of service in certain cases :

(1) Where a Development Officer has failed to conform to the expense limit and where no opportu-

nity to conform to such limit could be given under the provisions of rule 7, the Zonal Manager may terminate his services after giving him three months' notice or salary in lieu thereof :

Provided that the Development Officer shall be given an opportunity to show cause against the proposed termination of his services.

(2) An appeal against an order passed under sub-rule (1) shall lie to the Managing Director and the provisions of rule 41, 42, 43, 44 and 45 of the staff rules shall, so far as may be, apply to any such appeal.

(3) In the case of an appeal under sub-rule (2) the Managing Director shall consider the records of the case and pass orders on merits having regard to the circumstances of the case.

9. Deferment of Disincentives :

(1) The disincentives, other than "no increment", shall not be awarded from the relevant appraisal date (hereinafter referred to as "the relevant due date"), but shall be kept in abeyance until after the expiry of the succeeding year, if, in any preceding year a Development Officer, who has completed at least five years of service, has exceeded the prescribed expense limit attracting disincentives in accordance with the Table of Disincentives .

Provided that he has not exceeded the prescribed expense limit for a continuous period of not less than five years immediately preceding such relevant appraisal year or, where he has not completed five year of service but has completed at least three years of service and has not exceeded the prescribed expense limit in any year from the date of his joining as Development Officer.

(2) Where the Development Officer conforms to the prescribed expense limit in the succeeding year, referred to in sub-rule (1), no action shall be taken to award the disincentives which have been kept in abeyance, and if the increment, which would have otherwise accrued to him on the relevant due date, had been disallowed as a disincentive, such increment shall be released from the relevant due date.

(3) Where the Development Officer exceeds the prescribed expense limit in such succeeding year, the disincentives which have been kept in abeyance shall be awarded from the relevant due date and appropriate recovery of the excess remuneration paid to him in such succeeding year shall be made from his salary for the following year and the disincentive if any of "no increment" shall become final and he shall also be liable for action in accordance with the Table of Disincentives for his failure to conform to the prescribed expense limit in such succeeding year.

(4) Where the disincentives are not enforced or the increment is released from the relevant due date in accordance with sub-rule (2), the preceding year under sub-rule (1) will not be regarded as a year in which he has not exceeded the prescribed expense

limit for the purpose of computing the continuous service of five years or three years, as the case may be, in which he has not exceeded the prescribed expense limit.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if a Development Officer is at a stage where there is an efficiency bar, no increment shall be granted to him above that bar unless he has satisfied the requirements of rule 10.

10. Efficiency Bar :

(1) Where there is an efficiency bar in a scale of pay, a Development Officer shall not be certified fit to draw increments above that bar on or after 1st April, 1988, unless,—

- (a) his cost ratio with reference to his annual remuneration was not in excess of 20% in the appraisal year immediately preceding the relevant appraisal date (hereafter in this sub-rule referred to as the "relevant year");
- (b) he has not exceeded the expense limit applicable to him in the two appraisal years immediately preceding the relevant year.

(2) Where a Development Officer is allowed to cross an efficiency bar which has previously been enforced against him, he shall be allowed only one increment from a prospective date .

Provided that more than one increment may be allowed on removal of efficiency bar if he becomes eligible for any increment in accordance with rule 11, 12, 13 or 14.

(3) Where a Development Officer has crossed an efficiency bar but has been brought below that efficiency bar for any reason whatsoever, he may be allowed to cross that efficiency bar when he becomes eligible for his next increment, unless his increment has been withheld as a disciplinary measure under rule 39 of the staff rules.

11. Prospective restoration of reduction in basic pay in pursuance of Schedule III to the staff rules prior to the relevant appraisal date falling on or before 31-3-1988 :

(1) Where a Development Officer has conformed to the expense limit in the appraisal years relevant to the appraisal dates falling before 1st April, 1988 in the manner specified in this rule and he continues to conform to the expense limit thereafter, the reduction in his basic pay effected after 20th day of June, 1979, on the ground that he had exceeded the expense limit in any appraisal year in respect of which the relevant appraisal date was falling on or before 31st March, 1988 (such reduction in basic pay being hereinafter referred to as "past decrements") may be restored in accordance with the provisions of sub-rule (3) :

Provided that where a Development Officer qualifies for restoration of past decrements, the past dec-

rement which was first effected as a result of appraisal falling on the appraisal date subsequent to 20th day of June, 1979 shall first be restored, the past decrement which was effected thereafter shall be restored next and so on.

Explanation : For the purposes of this sub-rule, a past decrement pertaining to a year may consist of one stage or more than one stage in the scale of pay.

(2) The benefit of this rule shall accrue to a Development Officer only if he has conformed to the expense limit in the appraisal year immediately preceding the appraisal date falling on or after 1st day of April, 1987 but before the 1st day of April, 1988 (hereinafter referred to as the "central year") and the two appraisal years immediately preceding the central year and he shall continue to be eligible for the benefit of this rule so long thereafter as he conforms to the expense limit in the successive appraisal years next following the central year in chain and if the chain is interrupted by an appraisal year in which he fails to conform to the expense limit, he shall cease to get the benefit under this rule on and after the appraisal date relevant to such appraisal year.

Explanation : For the purpose of this rule, "chain" means a chain of three or more uninterrupted appraisal years in which the Development Officer has not exceeded the expense limit :

Provided that the appraisal year next following the central year or any appraisal year thereafter may be reckoned for the purpose of the said successive appraisal years if the cost ratio of the Development Officer in such appraisal year is not in excess of the expense limit by more than 2%.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4) and sub-rule (5) :—

- (i) where a Development Officer conforms to the expense limit on the first appraisal date falling on or after 1st April, 1987 in the central year and has to his credit a combined chain of three years the past decrements pertaining to one year may be restored from such first appraisal date.

Explanation : For the purposes of this sub-rule, "combined chain of three years", in relation to a Development Officer, means the central year and two appraisal years immediately preceding it in which he has conformed to the expense limit;

- (ii) if, besides a combined chain of three years, the Development Officer has to his credit a rear chain of three years or more than one such rear chain, the past decrements pertaining to as many years as there are rear chains of three years may be restored with effect from the first appraisal date referred to in clause (i);

Explanation : For the purposes of this sub-rule, "rear chain of three years", in relation to a Development Officer, means the appraisal year immediately preceding the central year and other uninterrupted

appraisal years preceding such appraisal year in chain in which a Development Officer has conformed to the expense limit;

- (iii) if the Development Officer has acquired to his credit a combined chain of three years but the past decrements cannot be restored in the absence of a rear chain of three years or the requisite number of such rear chains, and, if, on the relevant appraisal date relating to the appraisal year next following the central year, a special chain accrues to his credit, the eligible past decrements, if any, may be restored from such relevant appraisal date subject to the condition that where the reduction in basic pay pertaining to one year consists of more stages than one in the scale of pay, no restoration of eligible past decrement, shall fall due unless the prospective cost supports at least one stage in the scale of pay, but a Development Officer may qualify for restoration of the remaining stages of the reduction in basic pay pertaining to that year on the next occasion and on that occasion such remaining stages shall be deemed to be reduction in basic pay pertaining to one year.

Explanation : For the purposes of this sub-rule,—

- (a) "special chain", in relation to a Development Officer means the central year and the appraisal year immediately preceding and succeeding the central year in which a Development Officer has conformed to the expense limit;
- (b) "eligible past decrement" means the reduction in basic pay by one or more stages effected in one year, which or part of which, if restored, shall keep the prospective cost within ceiling;
- (c) "prospective cost" means the ratio which the annual remuneration applicable to a Development Officer on the relevant appraisal date (inclusive of all increments and proposed restoration on and from that date) bears to the eligible premium of the preceding year and the prospective cost shall be deemed to be within ceiling if such annual remuneration applicable to a Development Officer is not in excess of his expense limit percentage of such eligible premium;
- (d) "restoration" means the restoration of past decrement (by whatever name called).
- (iv) if any past decrements still remain to be restored after following the provisions of clauses (i) to (iii), further eligible past decrement for the relevant chain of three years may be restored from each of the respective appraisal dates on which he acquires a retro-progressive chain to his credit.

Explanation : For the purposes of this sub-rule,—

(a) “retro-progressive chain” in relation to any period beginning with the central year, means a chain of three years reckoned backwards from the relevant appraisal date to the beginning of the central year in which a Development Officer has conformed to the expense limit;

(b) “relevant chain of three years” means the chain of three years immediately preceding the relevant appraisal date which only shall be considered for the purpose of restoration of eligible past decrement on that date.

(4) If the Development Officer is at a stage in the scale of pay where there is an efficiency bar, no restoration shall be allowed unless he is eligible for crossing the efficiency bar in accordance with rule 10 in the appraisal year immediately preceding the appraisal date on which he may otherwise qualify for restoration.

(5) No restoration shall be allowed if, on restoration, the Development Officer shall reach a stage in the scale of pay which he would not have reached on the ground that he had exceeded the expense limit, and in such a case the restoration shall be limited to the stage in the scale of pay which he would have normally reached.

12. Prospective restoration of reduction in basic pay effected in pursuance of Schedule III to the staff rules prior to the relevant appraisal date falling on or before 31-3-1988—Alternative method :

(1) Subject to sub-rule (4) and sub-rule (5) of rule 11, if the cost ratio of a Development Officer does not exceed 15 per cent in the first or the second or the third appraisal year preceding the relevant appraisal dates falling on or after 1st April, 1989, but before 31st March, 1992, past decrements pertaining to one or more years in relation to appraisal dates falling on or before 31st March, 1988 may be restored in the manner specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 11, from the relevant appraisal dates to the extent the prospective cost remains within ceiling :

Provided that if the Development Officer is also eligible for any restoration in accordance with rule 11, he may opt for restoration either under that rule or this rule.

(2) For the purposes of this rule, the expressions “past decrements”, “restoration” and “prospective cost” shall have the same meaning as assigned to them in rule 11.

13. Reinstatement of reduction in basic pay effected in accordance with the Table of Disincentives as a result of appraisal where the relevant appraisal date falls on or after 1-4-1988 :

(1) The reduction effected in the basic pay of a Development Officer as a result of appraisal on the relevant appraisal date falling on or after 1st April,

1988 (hereinafter referred to as “current decrements”) may be reinstated in accordance with the provisions of this rule or rule 14.

(2) Where a Development Officer qualifies for reinstatement in accordance with this rule, the reduction in basic pay which was first effected on or after 1st April, 1988 shall first be reinstated; the reduction in basic pay which was effected thereafter shall be reinstated next and so on.

Provided that if a Development Officer fails to qualify for reinstatement within five appraisal years following the appraisal date from which his basic pay was reduced, there shall be no reinstatement of that reduction, and in that case the next reduction, if any, in basic pay shall be regarded as due for reinstatement if he subsequently qualifies for reinstatement :

Provided further that the reinstatement of reduction in basic pay under this rule and rule 14 shall be limited to only three occasions throughout the service as a Development Officer.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (4), if on any relevant appraisal date falling on or after 1st April, 1988, the appraisal discloses that a Development Officer has not exceeded the expense limit in the preceding year and that the cost ratio in such preceding year and the next two preceding years taken together does not exceed the combined expense limit for those three years (hereinafter referred to as a “block of three years”) the eligible current decrement may be reinstated with effect from the relevant appraisal date :

Provided that in any preceding year, a Development Officer does not conform to the expense limit, he may qualify for reinstatement if there arises a block of three years on any subsequent relevant appraisal date :

Provided further that current decrement pertaining to not more than one year shall be reinstated on one relevant appraisal date, even though the future cost may support reinstatement of decrements in excess of one year.

Explanation : For the purposes of this rule,—

(i) “block of three years” means every preceding year in which the Development Officer has not exceeded the expense limit and the next two preceding years;

(ii) “eligible current decrement” means the current decrement pertaining to one year which if reinstated shall still keep the future cost within ceiling;

(iii) “future cost” means the ratio which the annual remuneration applicable to a Development Officer on the relevant appraisal date (inclusive of all increments and proposed reinstatement on and from that date) bears to the eligible premium of the preceding year and the future cost shall be

deemed to be within ceiling, if such annual remuneration applicable to a Development Officer is not in excess of his expense limit percentage of such eligible premium.

(4) The provisions of sub-rule (4) and sub-rule (5) of the rule 11 shall, so far as may be, apply to reinstatement of reduction in pay as they apply to restoration of such reduction.

14. Reinstatement of reduction in basic pay effected in accordance with the Table of Disincentives as a result of appraisal where the relevant appraisal date falls on or after 1-4-1988. Alternative method :

Subject to the provisions of sub-rules (2) and (4) of rule 13, if a Development Officer does not exceed the expense limit in three successive appraisal years, the current decrement pertaining to one year may be reinstated with effect from the relevant appraisal date next following the last such appraisal year.

15. Provident Fund .

(1) Notwithstanding anything contained in rule 8 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, where the past decrements or current decrements are restored or reinstated to a Development Officer from the relevant appraisal date in accordance with the provisions contained in rule 11, 12, 13 or 14, the Corporation shall contribute to the Provident Fund established by it (hereinafter referred to as the "Fund") a maximum amount of 8½ per cent of the aggregate of the basic pay comprised in such decrements in relation to the period for which those decrements have been restored or reinstated :

Provided that if during the period of part of the period in which the said decrements were in force, the rate at which the employer's contribution was higher than 8-1/3 per cent, the Corporation may contribute at such higher rate on that part of the basic pay pertaining to the relevant period :

Provided further that the Development Officer shall contribute to the Fund an amount equal to the contributions required of the Corporation as his additional contribution in accordance with the rules of the Fund and in such manner as he may be directed by the Corporation.

(2) The Corporation shall credit its contributions to the Fund as and when and to the extent the Development Officer makes such additional contributions under the second proviso to sub-rule (1).

(3) The contributions made by the Corporation under sub-rule (1) shall not be available for any purpose for which the employer's contributions are not available under the rules of the Fund.

(4) Nothing contained in this rule shall apply to a Development Officer who is contributing to a superannuation fund approved by the Corporation.

16. Special Cases :

(1) The Managing Director may review any case and allow such relief, having regard to the merits of the case, to the Development Officer, if the Development Officer is not entitled to the benefit of rule 11 by reason only of his failure to conform to the expense limit in the central year :

Provided that the ratio which the aggregate of the annual remuneration for the central year and the two appraisal years next preceding bears to the aggregate of the eligible premium in those years does not exceed the expense limit :

Provided further that any such relief shall not exceed the benefit that would be available to the Development Officer had he qualified himself under rule 11.

(2) The Managing Director may, on the recommendation of the Zonal Manager, review any case of a Development Officer after the date of reduction in basic pay in pursuance of the Table of Disincentives if he does not qualify for reinstatement under rule 13 or rule 14 and grant such relief, having regard to the merits of the case, but not exceeding the relief that would have been admissible to him had he qualified himself under any of the said rules for reinstatement.

17. Incentives :

Incentive bonus under any scheme approved by the Corporation may be allowed to a Development Officer for any preceding year if his cost ratio with reference to his annual remuneration in that year does not exceed twenty per cent of the eligible premium of that year.

18. Promotion of Development Officer :

Any Development Officer considered suitable may be promoted as Assistant Branch Manager or Assistant Administrative Officer, in accordance with rule (7) of staff rules.

19. Re-appointment of terminated Development Officer :

If a Development Officer, whose services are terminated in pursuance of rule 8 has completed at least ten years of service in Class II on the date of such termination and has not completed 55 years of age, he shall be eligible for re-appointment in the service of the Corporation to do administrative work in Class III either as Assistant or Record Clerk in accordance with such qualification and suitability as may be specified under clause (cc) of sub-section 2 of section 48 of the Act.

Provided that notwithstanding the break in service as a consequence of termination, his service in the Corporation shall be deemed to be continuous for the purpose of leave; and also for the purpose of gratuity or Provident Fund if he has not received or if he has received but repays to the Corporation such amount of gratuity or Provident Fund as he has received.

20. Repeal and Savings :

(1) Schedule III of the staff rules, and the Life Insurance Corporation Development Officers (Alteration of Remuneration and other Terms and Conditions of Service) Order, 1978 are hereby repealed except in respect of things done or omitted to be done under the Schedule III to staff rules and Life Insurance Corporation Development Officers (Alteration of Remuneration and other Terms and Conditions of Service) Order, 1978 as so repealed.

(2) Nothing contained in these rules shall be deemed to affect the right of the Competent Authority to discharge, retire, or determine the service of a Development Officer in accordance with the staff rules or to affect the right of the disciplinary authority to impose any penalty on him under rule 39 of staff rules on any grounds specified therein or to apply the staff rules to Development Officers in respect of matters not dealt with in these rules.

21. Interpretation :

Where any doubt or difficulty arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for its decision.

[F. No. 2(60)/Ins. III/86]

N. R. RANGANATHAN, Addl. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise certain terms and conditions of service of Development Officers of the Life Insurance Corporation of India with effect from 1st April, 1988. The rules are accordingly given retrospective effect from 1st April, 1988.

2. It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.